

पंचायतों और निकायों में कोई छाप नहीं छोड़ पाया अफसरी राज

कटनी। प्रदेश में शायद यह पहला अवसर रहा जब लगातार डेढ़ दो साल से पंचायतों और नगरीय निकायों में जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व नहीं है। ग्राम पंचायतों में न पंच हैं ना सरपंच। जनपदों और जिला पंचायत भी अध्यक्ष और सदस्यों से खाली है तो वहीं नगरीय निकायों में भी परिषद अस्तित्वहीन है। जनप्रतिनिधियों की गैरमौजूदगी में पंचायतों और नगरीय निकायों के माध्यम से जनता को दी जाने वाली मूलभूत सेवाओं के सुचारु संचालन से लेकर विकास कार्यों के क्रियान्वयन तक का दायित्व सीधे तौर पर अधिकारियों के पास है। नगर निगम में खुद कलेक्टर प्रशासक के तौर पर पूरे काम काज की निगरानी कर रहे तो नगर परिषदें एस डी एम के हवाले हैं। पंचायतों में सचिवों का राज है। जनपदों और जिला पंचायत की बागडोर मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के हाथों में है। पंचायतों और निकायों की जिम्मेदारी संभाल रहे ये अधिकारी चाहते तो अपनी प्रशासनिक छमता से सिस्टम में कसावट लाकर सेवाओं को और बेहतर कर सकते थे साथ ही विकास कार्यों को गति देकर अपनी एक विशिष्ट छाप छोड़ सकते थे पर ऐसा हुआ नहीं। अधिकारियों ने इस जिम्मेदारी को अतिरिक्त बोझ समझते हुए इसके निर्वहन में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई जिसका परिणाम यह हुआ कि न तो सेवाएं ही बेहतर हुईं ना ही विकास कार्यों को गति मिल पाई। निकट भविष्य में पंचायत चुनावों की संभावना को देखते हुए उम्मीद की जा रही कि अगले साल की शुरुआत तक पंचायतों को अफसरी राज से मुक्ति मिल जायेगी पर नगरीय निकायों में अभी कम से कम छह महीने तक अफसरों का ही शासन रहने के आसार हैं।

जनप्रतिनिधियों की गैरमौजूदगी से बढहाल हुई सेवाएं

उत्खेनीय है कि जनवरी 2020 से लेकर मार्च 2020 तक प्रदेश में त्रि स्तरीय पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका था। सरकार ने भी पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने से लेकर आरक्षण निर्धारण तक की प्रक्रिया पूरी कर ली थी। बस पंचायत चुनावों का कार्यक्रम घोषित होना शेष था तभी कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण पूरे देश सहित प्रदेश में भी लॉक डाउन लगाया पड़ गया जिसके चलते पंचायत चुनावों की घोषणा नहीं हो सकी। इस बीच प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा की रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव करा लिए गए पर पंचायत चुनाव टलते ही चले गए। पंच-सरपंच नहीं होने से ग्राम पंचायतों में सचिवों का राज हो गया वहीं जनपद और जिला पंचायत का जिम्मा मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने सम्हाल लिया। अधिकारियों के इस राज में निरंकुशता हावी रही। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को बंटने वाले सस्ते खाद्यान्न सहित तमाम तरह की पेंशन और रोजगार मूलक कार्यों पर भी इसका असर दिखा। मनरेगा के कार्यों पर विराम लग गया। पंचायतों के माध्यम से कराये जाने वाले स्वीकृत विकास कार्य अधूरे रह गए। प्रधानमंत्री आवास जैसी महत्वपूर्ण योजना में जमकर बंदरबाट हुई। मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में ऐसी समस्याएं बहुतायत में आने लगीं। लोग सचिवों एवं अन्य अधिकारियों की शिकायत लेकर कलेक्टर के चक्र लगाते पड़े। जनसुनवाई में उमड़ने वाली भीड़ के चलते कलेक्टर को स्वयं जनपद मुख्यालयों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनने

के लिए बाध्य होना पड़ा। पूरे दो साल ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाने वाली सेवाएं और कराये जाने वाले विकास कार्य अधिकारियों के हवाले रहे। अब शासन ने त्रि स्तरीय पंचायत चुनावों की

आते आते पंचायती राज व्यवस्था पुनः पटरी पर लौट आयेगी। पंचायतों की तरह निकायों का कार्यकाल भी जनवरी 2020 में पूरा हो चुका है। सरकार और निर्वाचन आयोग ने

कलेक्टर को प्रशासक नियुक्त किया गया। तब से अब तक नगर निगम की सारी व्यवस्था उन्हीं के हवाले है। नगर की साफ-सफाई से लेकर सड़क, बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट, पर्वों पर विशेष व्यवस्थाएं सब कुछ उन्हीं के दिशा निर्देशन में चल रहा। व्यवस्थाएं चाक चौबंद होने के कितने ही दावे किए जाएं पर हकीकत यही है कि सेवाएं पहले से बेहतर नहीं हुईं बल्कि परेशानी और शिकायतें और बढ़ी हैं। चाहे सोवर लाइन के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरने से मासूम बच्चों की मौत का मामला हो या सड़कों की जर्जर हालत हो या फिर जगह जगह हो रहे अवैध निर्माण की शिकायतें हो हर जगह प्रशासनिक कसावट का अभाव साफ नजर आ रहा। नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं के स्तर में लगातार गिरावट आई है। अफसोस तो इस बात का है कि अभी भी नगरीय निकाय चुनाव जल्द होने के आसार नजर नहीं आ रहे। आरक्षण को लेकर दायर की गई याचिकाओं का निराकरण अभी नहीं हुआ। आरक्षण के लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंड पीठ के एक निर्णय के विरुद्ध सरकार सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। इस साल के अंत तक भी निकाय चुनाव हो पाने की उम्मीद नहीं दिख रही। कहा तो यहां तक जा रहा कि निकाय चुनाव के लिए अगले साल न केवल मतदाता सूची नई तैयार करनी पड़ सकती है बल्कि आरक्षण भी नए सिरे से करना पड़ सकता है। ऐसा हुआ तो अगले छह महीने तक निकाय चुनाव नहीं हो पाएंगे।



विकास कार्यों को भी नहीं मिली रफ्तार

तैयारियां फिर तेज कर दी हैं। जल्द ही जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण का निर्धारण होना है। आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होते ही चुनाव कार्यक्रम घोषित हो जाएगा। उम्मीद की जा सकती है कि अगले साल जनवरी तक त्रि स्तरीय पंचायतें पुनः बहाल हो जाएंगी। मार्च

निकाय चुनावों की तैयारी भी कर ली थी पर कोरोना के साथ-साथ आरक्षण को लेकर न्यायालयों में दायर की गई याचिकाओं ने निकाय चुनावों पर भी ब्रेक लगा दिया। कटनी नगर निगम में परिषद का कार्यकाल खत्म होने के बाद यहां जिले के प्रशासनिक मुखिया



ढंड में ऊलन वस्त्रों की नई वैरायटी लेकर तिब्बती वस्त्र विक्रेता कटनी आ चुके हैं। चोपाटी में इनकी दुकानें सज गई हैं।



गोसलपुर स्टेशन पर रुकी कटनी इटारसी मेमू ट्रेन।

पैसेंजर ट्रेनों में एक्सप्रेस का किराया वसूल रहा रेलवे

छोटे स्टेशनों में घंटों रोककर निकाला रहा मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों को

अधिक किराया देने के बाद भी परेशान हो रहे यात्री

कटनी। रेलवे द्वारा कुछेक पैसेंजर ट्रेनों में एक्सप्रेस का चार्ज यात्रियों वसूल किया जा रहा है। जिसमें सतना से कटनी आकर इटारसी की ओर जाने वाली मेमू पैसेंजर ट्रेन भी शामिल है। गाड़ी संख्या 06626 सतना से प्रतिदिन 12 बजकर 5 मिनट पर खाना होकर दोपहर 1 बजकर 55 मिनट पर कटनी आती है। इसके बाद कटनी से 06620 नंबर बनकर यह ट्रेन दोपहर 2 बजे कटनी से इटारसी की ओर खाना होती है। सतना से कटनी और कटनी से इटारसी तक यह ट्रेन सभी स्टेशनों पर रुकती है। इस दौरान कई मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों द्वारा इसे क्रॉस किया जाता है। जिससे मेमू ट्रेन को छोटे स्टेशनों पर रोकना पड़ता है। इस तरह यात्री एक्सप्रेस का किराया देने के बाद अपने गंतव्य में समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं। गोरतलब है कि पिछले

करीब डेढ़ साल से ट्रेनों में अतिरिक्त किराया देकर यात्रा करने के लिए मजबूर यात्रियों को राहत देते हुए रेलवे ने कुछेक पैसेंजर ट्रेनों में जनरल टिकट पर सफर करने की छूट दी है। इससे कटनी से छोटे स्टेशनों की यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा मिली है, लेकिन इन ट्रेनों में किराया साधारण की बजाए एक्सप्रेस का ही देना पड़ रहा है। इसमें कटनी से जबलपुर होते हुए इटारसी तक जाने वाली मेमू ट्रेन भी शामिल है। यह ट्रेन कटनी से जबलपुर और इटारसी के बीच प्रत्येक स्टेशन पर रुक रही है और इसमें किराया एक्सप्रेस की तर्ज पर लिया जा रहा है। यात्रियों का कहना है कि ट्रेन को जब पैसेंजर का दर्जा दिया गया है और यह सभी स्टेशनों पर रुक रही है तो फिर इसमें किराया एक्सप्रेस का क्यों लिया जा रहा है। इससे यात्रियों की जेब ढीली हो रही है।

फिर मिलाने लगे जनरल टिकट, सफर हुआ आसान

गोरतलब है कि देश भर में कोरोना के मामले घटने के साथ ही रेलवे ने यात्रियों के लिए अनारक्षित टिकट पर यात्रा करने की सुविधा को फिर से बहाल कर दिया है। अब जनरल कोचों और पैसेंजर ट्रेनों में यात्रा करने के लिए रिजर्वेशन नहीं कराने की जरूरत नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण के बाद यात्रियों के लिए जनरल कोच में भी रिजर्वेशन करवाना अनिवार्य था। इसकी वजह कोरोना की रफ्तार थामने के लिए भीड़ को नियंत्रित करना था लेकिन अब संक्रमण कम होने और देश भर में चले वैकसीनेशन अभियान के बाद रेलवे ने यात्रियों के लिए यह सुविधा फिर शुरू करने का फैसला लिया था। जिसके बाद कटनी रेलवे जंक्शन से जबलपुर रीवा जबलपुर शटल, जबलपुर रीवा जबलपुर इंटर्सिटी एक्सप्रेस, कटनी इटारसी कटनी मेमू पैसेंजर, मुड़वारा रेलवे स्टेशन से इटारसी बीना विंध्याचल एक्सप्रेस और कटनी बीना मेमू पैसेंजर ट्रेनों में यात्री जनरल टिकट पर यात्रा का लाभ उठा रहे हैं।

नगर परिषदों में रुके हैं विकास कार्य

जिले की तीन नगर परिषदों कैमोर, विजयराघवगढ़ और बरही का कार्यकाल भी जनवरी 2020 में खत्म हो गया था। यहां एस डी एम को प्रशासक नियुक्त किया गया। कोविड के दौरान चाहे यात्रा की अनुमति लेनी हो या शादी ब्याह की लोग एस डी एम के चक्र ही लगाते रहे। कोरोना की लहर खत्म होने के बाद भी महीनों साप्ताहिक बाजारों को बंद रखा गया। कैमोर नगर परिषद में बस स्टैंड निर्माण के लिए भूमिपूजन के एक साल बाद भी कोई काम शुरू नहीं हो सका। पतिहाई धाम के विकास कार्य की फाइल भी अटकी रही। कैमोर और बरही में लंबे समय तक कोई सी एम ओ नहीं रहा। इन सब बातों से नगर परिषदों के अनेक विकास कार्य आगे बढ़ ही नहीं पाए जो शुरू हुए भी उनमें अधिकारीराज की उदासीनता साफ झलके रही। ऐसे में सेवाओं और विकास कार्यों की सुध लेने वाला भी कोई नहीं है। अधिकारी चाहें तो छह महीने के इस समय में वे अपनी कार्य कुशलता और प्रशासनिक छमता से निकायों के हालात बदल सकते हैं।

अधिक खबरों के लिए लॉगिन करें www.yashbharat.com

दुनिया का नं.1 ब्रांड **SAMSUNG**

UP To 22.5% Additional Cash Back 0% Finance Scheme Exchange Offer

Upsize your lifestyle with amazing offers.

Free Sound Bar 9990/- For Selected TVs

आयुष प्लाजा
सेमसंग एक्सवैल्यूसिव शोरूम
विशाल मेगा मार्ट के पास बरवावा कटनी, मो. 9893366435, 8319908847

यदि आप तक समय पर यश भारत नहीं पहुंच रहा है तो संपर्क करें फोन- 230033

रत्ना मेरिज गार्डन
मुड़वारा स्टेशन के पास पानी, बिजली और पार्किंग की बेहतर व्यवस्था

शहर के मध्य सुविधाओं से युक्त विशाल परिसर

बजट आपका व्यवस्था हमारी
एक बार अवश्य पधारें

शहर के मध्य क्षेत्र में मीटिंग, कान्फ्रेंस, बर्थ-डे पार्टी एवं अन्य बड़े आयोजनों के लिए बेहतर स्थान

शादी विवाह व अन्य आयोजन के लिए 100 व्यक्तियों के दहसरे की उत्तम व्यवस्था, जनवारा अलग से

पाठक वाई, कटनी
संपर्क :- 9425466630, 7999523588

कोरोना गाइड लाइन के तहत ही सभी कार्यक्रम का आयोजन होगा

इयूरेबल डिजाइनर फर्नीचर की फुल रेंज

अब है स्मार्ट फर्नीचर का जमाना

FURNIT
THE FURNITURE HUB...

गोरी शंकर मंदिर के पास, खेबर लाइन, माधव नगर कटनी (म.प्र.)

- Call - 9770037027

पोस्ट कोविड समस्याओं के सही इलाज के लिए मिलें Pulmonologist

डॉ. रिमिता बजाज

MBBS, DTC, CCEDM

टी.बी., दमा, र्वासा, खांसी, एलर्जी एवं अयबटोज स्पेशलिस्ट

मोसम बदलने पर बार-बार खांसी आना, साल भर सर्दी बने रहना, एलर्जी की शिकायत होना एवं नॉंद में सीटी की आवाज आना

नोट- स्पायरोमीट्री (फेफड़ों की कम्प्यूटरीकृत जांच) एवं (एलर्जी टेस्टिंग) की सुविधा उपलब्ध है।

संपर्क करें- डॉ. राजीव बजाज (शिशु रोग विशेषज्ञ)

कन्हैया हॉस्पिटल, माई नदी के पास बरही रोड, कटनी
फोन-07622-236253, मो. 6266203009

CITY Mall
EVERYTHING UNDER ONE ROOF
AVAILABLE FACILITIES

ASSOCIATED WITH

BIG BAZAAR, Reliance digital, TRENDS GET THEM TALKING

PLANET FASHION, U-TURN, BOLSA

FLAVOURS, GRAVITY THE PUB

City Mall, Near Main Railway Station, Barhi Road, Katni (M.P.)
Phone : +91 7622 422408, email : citymallkatni@gmail.com

Katni's No. 1
M. 94258 01294

मंजूश्री
LIFESTYLE

कोट सूट। शेरवानी। इंडो वेस्टर्न। ब्लेजर। कुर्ता जैकेट

पता- खिरहनी ओव्हरब्रिज के पास हीरागंज, कटनी (म.प्र.) 483501